

कर रहे हैं जहाँ गैस और खनिज पदार्थ, रॉ-मैटीरियल वहाँ उपलब्ध है सब के सब जितना वहाँ उत्पादन होगा उस देश में एक छट्ठा भी नहीं रहेगा पूरा उत्पादन हमारे देश में आ जाएगा। इस तरह से अभी हमारी जितनी आवश्यकता है एक-दो साल के अंदर जितना चाहिए उतना तो हम देंगे ही, हो सकता है कि अधिक भी हो जाए इससे हम रोज बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं।

Bird menace at IGIA

*543. SYED SIBTEY EAZI:
SHRI SATYA PRAKASH
MALAVIYA:

Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether incidents of birds hitting the Air India aircraft at the Indira Gandhi International Airport are increasing rapidly;

(b) if so, the details thereof in chronological order from 1st January 1994 to 18th April, 1994;

(c) whether such incidents are also increasing at other air bases of the country;

(d) if so, the details thereof State and Union Territory-wise, from 1st January, 1993 to 18th April, 1994;

(e) whether such incidents are threatening the safety of air passengers seriously;

(f) whether Government propose to take some measures promptly; and

(g) if so, the details thereof and if not the reasons therefor?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) to (g) A statement is laid on the Table of the House.

†The question was actually asked on the floor of the House by Syed Sibtey Razi,

Statement

(a) No, Sir.

(b) 13.1.94, Air India B-747 aircraft after take off from IGI Airport was hit by a bird causing damage to No. 1 engine. In the second incident on 15.4.94, the No. 2 engine of an Air India aircraft B-747 was damaged after a bird hit.

(c) The number of bird hits at airports all over India has decreased from 189 in 1986 to 128 in 1993.

(d) the requisite information is furnished in the Statement-I (See below).

(e) Yes, Sir.

(f) and (g) The following measures have been taken to reduce the incidence of bird-hits to aircraft in and around airports: —

(i) Airfield Environment Management Committees have been established at airports to monitor the implementation of measures to control bird menace.

(ii) Officials of the Directorate of General of Civil Aviation (DGCA) in association with the airport authorities, airlines and municipal and health authorities periodically carry out joint surveys of the areas surrounding major airports to identify the sources of bird attraction, suggest remedial measures and detect instances of violation of laws and regulations,

(iii) Prosecution is initiated under Aircraft Rules against persons indulging in skinning of dead animals and slaughtering of animals and disposal of garbage in the open which attract birds in the vicinity of the aerodrome.

(iv) Proper disposal of food wastes and garbage originating from flight kitchens and aircraft inside the aerodrome is ensured.

(v) Levelling oil airfield operational and pigeon proofing of hangars inside the area, removal of wild vegetation, aerodromes etc. are undertaken.
provision of proper drainage

Statement-I

Bill hits to aircraft at different airports, State and Union Territory-wise, in India from 1-1-93 to 18-4-94 are as given below :-

State/Territory	Airport	Bird hits
Delhi		25
Goa		2
U.P.	Lucknow	1
	Varanasi	5
Bihar	Patna	3
	Ranchi	1
	Jamshedpur	0
Andhra Pradesh	Hyderabad	9
	Vijayawada	0
	Vizag	0
Tamil Nadu	Madras	10
	Trichy	0
	Madurai	1
	Coimbatore	2
Kerala	Trivandrum	3
	Calicut	3
	Cochin	1
Karnataka	Bangalore	6
	Mangalore	1
Orissa	Bhubaneswar	2
Maharashtra	Bombay	17
	Aurangabad	2
	Nagpur	1
	Nasik	0
	Pune	0
Gujarat	Ahmedabad	6
	Baroda	2
	Bhuj	0
	Rajkot	3
M. P.	Bhopal	1
	Khajuraho	3
	Indore	2
	Raipur	0
Rajasthan	Jaipur	4
	Jodhpur	1
	Udaipur	1
Jammu & Kashmir	Srinagar	2
	Jammu	1
Punjab	Amritsar	1
	Chandigarh	0
West Bengal	Calcutta	12
	Bagdogra	3
North-East	Guwahati	2
	Dibrugarh	2
	Silchar	1

सैयद सिद्दीक रज़ी : सर, जवाब के "बी" पार्ट में माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि 15 अप्रैल, 1994 को दिल्ली में एक हादसा हुआ था जिसमें कि एअर इंडिया का टू एंजिन एअरक्राफ्ट हैमोज हुआ था पक्षी के टकरा जाने से। मैं मंत्रीजी का ध्यान 17 अप्रैल के हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ दिलाना चाहूंगा और उनके इजी रिफरेंस के लिए कोट करना चाहूंगा—

"With the city's abattoir closed and a mushroom growth of illegal slaughter houses in the vicinity of the Indira Gandhi International Airport, the traffic of birds over Delhi has increased manifold threatening the aircraft."

شری سید سبط الرحمن : مسلسل جاری ہے ؛
دوسرے میں یہ جاننا چاہوں گا پرنسپل کویشن
کی بات کوئی ہے پارٹ تین میں تو ایسے
کمیشنر کتنے وائٹیشن کے یہاں پہنچتے ہیں
گاریج پھینکنے کے یا ٹیڈ ان میل یا کچھ اس
طرح سے سلائنگ وغیرہ کے ایسے کتنے وائٹیشن
کے کمیشنر ہوتے ہیں اور ان میں سے کتنی کتنی
کوئی کیشن ہوتی ہے ؟ میں ماننا نہیں کرتی ہی
سے یہ جاننا چاہوں گا ۔

और एक बात कहना चाहूंगा ।

اور انکے اسی دہدونس کے لئے کڑت
کڑنا چاہوں گا ... اور ایک بات
کہنا چاہوں گا -

"Meanwhile, the official of DGCA and the National Airports Authority have appealed to the police of Delhi and Haryana to have an effective control over illegal slaughter houses around the airport area."

† [] Transliteration in Arabic Script.

सर, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि जो परिस्थिति अभी दिल्ली में उभर कर आयी है एक हाईकोर्ट के जजमेंट की वजह से कि स्लॉटर हाउस दिल्ली में बंद हो गया है और उसके कारण हजारों-हजार हमारे कुरेसी बिरादरी के भाई बेकार हो गए हैं। साथ ही यह मशरूम ग्रोथ भी हो रही है, जैसे कि अगर आप लीकर बैन कर दें तो इलिसिट लीकर बनने लगती है, बिल्कुल इसी तरह से यह हो रहा है। तो माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उनका मंत्रालय दिल्ली प्रशासन, दिल्ली के मुख्य मंत्री या जो और जिम्मेदार लोग हैं उनसे इस सिलसिले में कुछ बातचीत कर रहे हैं कि स्लॉटर हाउस जल्दी से खोले क्योंकि इसकी वजह से यह मशरूम ग्रोथ एअरपोर्ट एरिया के चारों तरफ हो रही है और जिसके कारण एअर से यात्रा करने वाले यात्रियों की जान जोखिम में पड़ जाती है। तो इस सिलसिले में वह क्या कर रहे हैं, कृपया बताएं? सर, आज की परिस्थितियाँ बदल गयी हैं। पहले एअरपोर्ट शहर के बाहर हुआ करते थे, अब करीब-करीब बहुत से एअरपोर्ट्स शहरों के अंदर चले आ रहे हैं। सर, खास तौर से यदि हम शांताकुज बॉम्बे एअरपोर्ट को देखें तो उसके चारों तरफ झुग्गी-झोंपड़ियाँ बन गयी हैं और क्योंकि जहाँ मनुष्य रहते हैं वहाँ खाने-पीने की चीजें फेंक दी जाती हैं जिसके कारण वहाँ चील, कौवे और दूसरे पक्षी आते-जाते रहते हैं।

MR. CHAIRMAN: The Minister has already given the reasons. Please conclude now.

सैयद सिद्दीक रज़ी : सर, मैं जानना चाहूंगा कि मंत्रीजी इस मीनेस को फेंस करने के लिए क्या कर रहे हैं? दूसरे, जैसाकि इन्होंने कहा कि हादसों में कमी हुई है और 189 से वर्ष 1993 में यह घटकर 128 हो गयी है। सर, मैं कहना चाहूंगा कि हादसे कितने हुए उससे यह मेटर करता है कि हादसों

†[] Transliteration in Arabic Script.

में कोर्ट में इस मामले पर चर्चा और निर्णय होने वाला है। इसलिए मैं नहीं समझता कि आज इस विषय में कुछ कहना चाहिए। इसके अलावा अभी सिविल एक्शन सेक्रेटरी ने हरियाणा और बाकी नजदीक के गवर्नमेंट्स को लिखा है कि उनको तुरन्त इस बारे में कार्यवाही करनी चाहिए। जहां तक हमारे मंत्रालय का सम्बंध है, जैसाकि मैंने अपने उत्तर में बताया है कि बहुत सारी कमेटीज हैं। हर एयरपोर्ट के लिए एक कमेटी बनायी गयी है। जहां तक दिल्ली, बंबई, कलकत्ता और हैदराबाद का संबंध है, जहां कि इस तरह की बड़ मिनस ज्यादा हैं, वहां के लिए एक्शन प्लान बनाया गया है जिसमें कि लोकल अथॉरिटीज के सीनियर ऑफिसर्स रहते हैं, जैसेकि दिल्ली में डबलपमेंट कमिशनर चेयरमैन हैं, उसके नीचे एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑफिसर्स, एयरलाइंस के ऑफिसर्स और म्युनिसिपल कार्पोरेशन के ऑफिसर्स रहते हैं। बॉम्बे में एन-वायरनमेंट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में इसी तरह की कमेटी है। इसके साथ-साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग भी होती है। तो ये नभाम प्रयास किए जा रहे हैं सिविल एक्शन मिनिस्ट्री की तरफ से और यही कारण है, जैसाकि मैंने अपने उत्तर में बताया है, 1986 में जबकि यह 189 थी, आलमोस्ट 190, आज 199.3 में यह 128 है और तकरीबन पिछले 8 सालों में बड़ हिट की संख्या 71 कम हो गयी है जबकि एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स आलमोस्ट 40 परसेंट बढ़ गए हैं और बड़ हिट तकरीबन 30-40 परसेंट कम हो गया है। तो यह प्रयास सरकार की तरफ से जारी है और यह एक ऑन-गोइंग प्रोसेस है जोकि एक दिन में खत्म होने वाली चीजें नहीं हैं जिनमें पेट्रोलिंग और दूसरी चीजें हैं। फिर जहां तक आपने स्लॉटर हाउस के संबंध में फरमाया, मेरे पास उत्तर है, लेकिन यह सबजुडिस्ट होने के कारण मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा।

हैदर सिद्दीकी रज़ी: सर, माननीय मंत्री जी ने कमेटीज और एक्शन प्लान के बारे में कहा है। मैं जानना चाहूंगा

कि यह कब बनाया गया है और क्या उसका क्रियान्वयन शुरू हो गया है? दूसरे मैं यह जानना चाहूंगा प्रोसीक्यूशन की बात कही है पार्ट तीन में, तो ऐसे केसेज कितने वायलेशन के यहां पर हुये हैं गारवेंज फेंकने के या डैड एनीमल या कुछ इस तरह से स्लाइटिंग वगैरह के? ऐसे कितने वायलेशन के केसेज हुये हैं और उनमें से कितनी कंवीक्शन हुई हैं? मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा।

† [شری سید سبط رحمتی: (مسائل جاری) : دوسرے میں یہ جاننا چاہوں گا - پروسیکوشن کی بات کہی ہے پارٹ تین میں تو ایسے کہسز کے لیے وائیلیشن کے یہاں پر ہوئے ہیں گارڈیج پیمنٹس کے بارے میں ڈیڈ انمل یا کچھ اس طرح سے سلائیٹنگ وغیرہ کے ایسے کے لیے وائیلیشن کے کہسز ہوئے ہیں اور ان میں سے کتنی کتنی کلمپیکشنس ہوئی ہوں۔ میں مانتا ہوں -] [

श्री गुलाम नबी आजाद: सर, जहां तक एक्शन प्लान का संबंध है, एक्शन प्लान जैसे मैंने अर्ज किया, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और हैदराबाद के लिये शुरू हो गया है। दिल्ली का 1985 में हुआ था, बम्बई का 1986 में हुआ और मुझे खुशी है यह कहते हुये कि इस एक्शन प्लान में, दिल्ली के एक्शन प्लान में तकरीबन छह-सात आइटम थीं, जिनमें से एक को छोड़कर सभी हुई हैं। पहला था - checking of illegal

visiting around the airports. यह तो एक कंटीन्यूस प्रोसेस है और इसके लिये एक बाडी बनी है। जैसा मैंने अर्ज किया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी और म्युनिसिपल कारपोरेशन के सभी आफीसर हैं। दूसरा - shifting of dairy farms from the vicinity of airports. इसमें से दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेशन ने

बहुत सारे डेरी फार्म शिफ्ट किये हैं। तीसरा था—

The proper disposal of garbage and meat and fish wastes from the marketing establishments and slaughter

houses.

इसका भी आपको मालूम होगा, बसन्त विहार, बसन्त कुंज और आर.के. पुरम के गारबेज डंप जितने भी थे उनको कवर किया गया वायर नेट्स के साथ।

Setting up of carcasses utilisation centre in the modern slaughter house at Delhi.

एडमिनिस्ट्रेशन ने करना था और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे मंत्रालय की तरफ से उस वक्त बताया गया था कि इसकी जो कैपिटल कोस्ट होगी वह सिविल एविएशन मिनस्ट्री के डिफरेंट आर्गेनाइजेशन, देगे एयर इंडिया, इंडियन एयर लाइंस, एअरपोर्ट अथोरिटी और इंटरनेशनल एअरपोर्ट अथोरिटी, लेकिन जगह और बनाने का काम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने करना था, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। उसका कारण है कि कई गढ़ उन्होंने चन सी और नर्वा फैसला

covering the

garbage dumps with wire-mesh.

जैसा मैंने अर्ज किया, पहले ही कर चके हैं।

The next is levelling the airfield and pigeon proofing of hangars.

नैवलिंग और ग्रेडिंग एअरपोर्ट की होगी।

... (व्यवधान)

MH. CHAIRMAN: I think the Minister has mentioned all these things in the written answer. (Interruptions) ... I think the Minister has already answered these things (Interruptions). . He has given Very adequate answers.

SHRI GHULAM NABI AZAD: In the last part the hon. Member has said,

कि कितने केसेज हुए हैं। अभी 21 तारीख को, दिल्ली पुलिस स्टेशन ने एक 15,16, 17 को जवाब दे सके की थी और 21 तारीख को कौन पुलिस स्टेशन ने तकरीबन तीन आदमियों को अरेस्ट किया है और वह अभी 14 दिन की जूडिशियल कस्टडी में हैं।

SHRI SIKANDER BAKHT: Since the question of slaughterhouse has come up, I would like to ask the hon. Minister whether he would like to approach the Cabinet and not the Delhi Government because it is not the Delhi Government alone which needs to have a proper slaughterhouse. It is an all-India question. Will the Minister approach the Cabinet to find out whether they have any scheme for constructing underground slaughterhouses as there is absolutely no alternative to the construction of underground slaughterhouses all over the country?

SHRI GHULAM NABI AZAD: As far as the Civil Aviation and Tourism Ministry is concerned, we have offered our services to the Delhi Municipal Corporation. Let them construct the modern slaughterhouse and we will bear 50 per cent of the capital cost of that organisation. For the benefit of the hon. Member...

SHRI SIKANDER BAKHT: Will you approach the Cabinet?

SHRI GHULAM NABI AZAD: For the benefit of the hon. Member I would like to say that, according to the information given by the Municipal Health Officer, MCD the site at Narela as been given a 'No Objection Certificate' by the Delhi Pollution Control Board and, according to the MCD, it was proposed...

SHRI SIKANDER BAKHT: He is restricting my question to Delhi alone. Would you like to approach the Cabinet for a scheme to have underground slaughterhouses throughout the country? (Interruptions)...

Will you approach the Central Government (Interruptions).

SHRI GHULAM NABI AZAD: It is ultimately the Delhi Administration who will have to do it. We are going to the extent of providing 50 per cent of the total money for the capital,

श्री सिकन्दर बख्त : मेरी गुजारिश यह है कि क्या आप मरकजी सरकार तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे कि तमाम मुल्क में अंडरग्राउंड स्लाटर हाउसिस बनायेंगे ? सिर्फ दिल्ली का सवाल नहीं, यहां क्या होगा?

شری سکندر بخت : میری گزارش یہ ہے کہ کیا آپ مرکزی سرکار تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تمام ملک میں انڈر گرائونڈ سلاٹر ہاؤسز بنائیں گے۔ صرف دہلی کا سوال نہیں، یہاں کیا ہوگا۔

श्री गुलाम नबी आजाद : यह सिविल एविएशन के हिसाब से नहीं, हम तो वालेंटी तौर पर क्योंकि इसमें बड़े हिट का सवाल है, तो उस स्पेसिफिक चीज के लिये हम मदद कर रहे हैं वरना सिविल एविएशन मिनिसट्री की तो कोई ज्यूरिडिक्शन ही इसमें नहीं है। यह तो खाली क्योंकि स्लाटर हाउसिस डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कनेक्टिड है विद दि बड़े हिट।

To that extent we are offering our services. Otherwise, we are not involved in it.

SHRI SIKANDER BAKHT: What should we do? (Interruptions). Sir, would the Minister approach the Central Government for having underground slaughterhouses all over the country? (Interruptions).

THE PRIME MINISTER (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): Sir, I would like to submit that whenever the Civil

Aviation authorities feel, wherever in India, that there is a possibility of a bird hit because of the presence of a slaughterhouse in the vicinity of their airport, naturally they will take it up with the Central Government. This can be done. We can generally ask the State Governments to have underground slaughterhouses. But if it is general in which they are not concerned at all... (Interruptions). Let me answer. I am prepared to respond to your request. Please write to me and I will certainly respond to it. Please don't ask to the wrong Minister because he is only concerned with Civil Aviation.

श्रीमती चन्द्रकांता पांडेय : सभापति महोदय, मेरा प्रश्न बहुत कुछ साहित्य से संबंधित है और उड़ान से भी। बचपन में मैंने एक कविता पढ़ी थी, जो आज भी पढ़ाई जाती है:—

ऊपर, ऊपर, ऊपर, ऊपर, उड़ा चला
जा रहा जहाज,
नहीं मुकाबला कर सकते हैं चील,
गिद्ध, कौबे और बाज

बच्चे इसे आज भी पढ़ते हैं और जब ऐसी घटनायें सुनते हैं तो उनके मन में प्रश्न उठता है कि चील, कौबे, बाज और गिद्ध के पंखों से आज जहाज क्यों टकरा रहे हैं ? आज असलियत की कड़वाहट हमारे सामने है। मैं पूछना चाहती हूं माननीय मंत्री जी से कि क्या अब हमारे विमान पक्षियों तक से हार गये हैं और इंडियन एयरलाइंस के विमान तब-जब उनके पंखों से टकराते हैं और इस तरह हजारों लोगों के जीवन को दांव पर लगा रहे हैं, कृपया बतायें कि तत्काल इस भौतिक विपत्ति से लड़ने का आपने क्या इंतजाम किया है?

उड़ान में भारतीय वैज्ञानिकों की अंतरिक्ष उड़ान की उपलब्धि की सराहना करते हुये कहना चाहूंगी कि विमान भी तो

उनके अंतरिक्ष में ही उड़ान की सफलता है। इस उड़ान की सुरक्षा पर हजारों की जानें निर्भर हैं, कृपया हमें कोई सकारात्मक उत्तर दें। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Why do we go so back? We can go back to Rama-yana. Rawana also defeated Jatayu.

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, it was basically their territory which we have encroached in the modern age. But this is a worldwide phenomenon. It is not there Only in our country. Of course, keeping in view the general culture as it is in our country, we have more bird hits as compared to the rest of the world. Then you cannot say that; this is the only area because in our surroundings we have hutments and we don't have cleanliness to the extent which other countries have.

SHRI JOHN F. FERNANDES: Sir, the problem of bird-hits in some other countries is solved by using certain species of birds called African Falcon. In our country this bird is not permitted to be imported by the Ministry of Environment and Forests because the Minister wants to protect wildlife. He has compassion for the wildlife I have no objection to that. But the Minister of Civil Aviation should also have some concern for human lives.. May I know from the hon. Minister whether this particular bird will be permitted to be imported in our country for a specific purpose as a special case? He has compassion for wildlife.

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, some countries are making use of this particular bird. But we are being told that it is no more successful As far as our country is concerned. Some time back, an attempt was made to do it. But at that time the Ministry of Environment did not allow it. That is why, it is not being done.

MR. CHAIRMAN: Question No. 544.

Inflow of FDI in the country

*544. SHRI G. G. SWELL: SHRI CHIMANBHAI MEHTA:t

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the number of Foreign Direct Investment proposals approved since 1991, yearwise figures of amount involved in FDI proposals and invested so far;

(b) what is the actual inflow of FDI, till date;

(c) what are the more beneficial tax concessions to FDI as compared to Indian and NRI investment;

(d) what are the industries where 100 percent and 50 percent FDI is allowed, separately; and

(e) whether there is a proposal for 75 percent FDI equity to be approved automatically?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) Number and amount of foreign direct investment proposals approved since 1991 to 1994 (up to March) areas under:—

(Rupees in crores)

Year	No. of Foreign direct Investment proposals approved	Amount of Foreign direct Investment approved
1991	289	534.11
1992	692	3887.54
1993	785	8859.33
1994 (up to March, 1994)	211	1175.10

†[1 The question was actually asked on the floor of the House by Shri Chimanbhai Mehta.